

## सतत् शहरीकरण की ओर

यह एडिटरियल 28/05/2024 को 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित [“Fires in Rajkot and Delhi: To get safer cities, we must demand them”](#) लेख पर आधारित है। इसमें भारत के शहरी परदृश्य से संबंध चुनौतियों और शहरी परदृश्य को पुनर्जीवित करने के लिये आवश्यक रणनीतियों की चर्चा की गई है।

### प्रलमिस के लिये:

[शहरों का वसितार एवं विकास, नगर नगिम, 74वाँ संवधान संशोधन अधिनियम, 1992, वशिव वायु गुणवत्ता रपिर्ट 2023, नगरीय ऊष्मा द्वीप प्रभाव, शहरी आग, शहरी बाढ़, स्मार्ट शहर, AMRUT मशिन, स्वच्छ भारत मशिन-शहरी, प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी, आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम](#)।

### मेन्स के लिये:

भारत में शहरों से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ, भारत में शहरी शासन की रूपरेखा।

भारत का [शहरी परदृश्य \(Urban Landscape\)](#) परिवर्तनकारी विकास के दौर से गुज़र रहा है। देश भर के शहर आर्थिक गतिशीलता से प्रेरित होकर तेज़ी से विकास कर रहे हैं। हालाँकि, इस तीव्र वसितार ने शहरी स्थानों (urban spaces) की गुणवत्ता एवं संवहनीयता के बारे में एक महत्वपूर्ण वमिर्श को जन्म दिया है।

घाटकोपर और पुणे में वशाल होर्डिंग्स का गरिना, डोंबविली में एक रासायनिक कारखाने के बॉयलर में वस्फोट, राजकोट के गेम ज़ोन में आग लगना तथा नई दल्लि के एक बाल चिकित्सा अस्पताल में ऑक्सीजन सिलिंडर वस्फोट जैसी हाल की घटनाएँ सुरक्षा संबंधी मौजूदा चिंताओं को उजागर करती हैं।

- इस परदृश्य में, भारत में शहरी नयोजन के लिये एक ऐसे सूक्ष्म दृष्टिकोण को अपनाना समय की मांग है जो [आर्थिक विकास, सुरक्षा और नागरिकों के हित के बीच संतुलन स्थापित](#) करता हो।

## भारत में शहरी शासन से संबंधित ढाँचा

- **संस्थाएँ:**
  - **आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA):** यह राष्ट्रीय नीतियाँ तैयार करता है और शहरी विकास से संबंधित केंद्र सरकार की योजनाओं की देखरेख करता है।
  - **शहरी विकास से संबंधित राज्य के वभिग:** ये केंद्र सरकार की नीतियों को लागू करने और राज्य-वशिष्ट शहरी विकास वनियमनों के नरिमाण में भूमिका नभिते हैं।
  - **नगर नगिम/नगरपालिकाएँ:** वे अपने क्षेत्राधिकार में स्थानीय स्तर के योजना-नरिमाण, विकास नयितरण और सेवा वतिरण के लिये ज़मिमेदार हैं।
  - **शहरी विकास प्राधिकरण (UDAs):** ये वशिष्ट शहरी क्षेत्रों या परयोजनाओं के विकास के लिये स्थापित वशिष एजेंसियाँ हैं।
- **संवैधानिक और वधिक ढाँचा:**
  - **भारतीय संवधान (अनुच्छेद 243Q, 243W):** यह स्थानीय सरकारों (नगर नकियों) को उनके क्षेत्राधिकार में शहरी नयोजन और विकास के लिये सशक्त बनाता है।
  - **74वाँ संवधान संशोधन अधिनियम, 1992:** इसके माध्यम से शहरी स्थानीय नकियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और संवधान में भाग IX-A को शामिल किया गया।

## भारत में शहरों से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ

- **अपर्याप्त आवास और मलिन बस्तियों का प्रसार:** आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2012-27 के बीच भारत में शहरी आवास की कमी लगभग 18.78 मिलियन इकाई थी, जहाँ 65 मिलियन से अधिक लोग झुग्गी-झोपड़ियों या अनौपचारिक बस्तियों में रहे थे।

- **वायु प्रदूषण और पर्यावरण क्षरण:** भारत के शहरी क्षेत्र गंभीर वायु प्रदूषण स्तर से जूझ रहे हैं, जिसका मुख्य कारण वाहनों से निकलने वाला उत्सर्जन, औद्योगिक गतिविधियाँ और निर्माण परियोजनाएँ हैं।
  - उदाहरण: [वर्ल्ड वायु गुणवत्ता रिपोर्ट \(World Air Quality Report\), 2023](#) के अनुसार विश्व के शीर्ष 10 प्रदूषित शहरों में से 9 भारत में हैं।
- **यातायात भीड़ और परिवहन संबंधी चुनौतियाँ:** तीव्र शहरीकरण और नजीक़ी वाहनों के बढ़ते चलन के कारण [यातायात भीड़](#) बढ़ गई है, यात्रा समय की वृद्धि हुई है और उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
  - उदाहरण: बेंगलुरु में व्यस्त समय के दौरान यातायात की औसत गति लगभग 18 कमी/घंटा आकलित की गई, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादकता में कमी और ईंधन की बर्बादी के कारण महत्वपूर्ण आर्थिक हानि होती है।
- **अपर्याप्त ठोस अपशिष्ट प्रबंधन:** भारतीय शहर [ठोस अपशिष्ट](#) के प्रबंधन के मामले में संघर्ष कर रहे हैं, जिसके कारण कूड़े का ढेर लग जाता है और स्वास्थ्य संबंधी खतरे उत्पन्न होते हैं।
  - उदाहरण: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, भारतीय शहरों में प्रतिवर्ष लगभग 62 मिलियन टन ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है, जिसमें से केवल 20% का ही उपयुक्त तरीके से प्रसंस्करण या उपचार किया जाता है।
- **साइबर सुरक्षा और प्रत्यास्थ डिजिटल अवसंरचना संबंधी मुद्दे:** प्रमुख शहरी स्थानों में बढ़ते डिजिटलीकरण के साथ [डिजिटल खतरे](#) बढ़ रहे हैं और प्रत्यास्थ डिजिटल अवसंरचना का निर्माण एक गंभीर मुद्दा है।
  - **AIIMS, दिल्ली पर वर्ष 2022 में हुआ रैनसमवेयर हमला** शहरी डिजिटल प्रणालियों की भेद्यता को उजागर करता है।
- **जल की कमी और अपर्याप्त जल प्रबंधन:** कई शहरों को तीव्र शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि और घटते भूजल स्तर के कारण [जल की गंभीर कमी](#) का सामना करना पड़ रहा है।
  - उदाहरण: चेन्नई को वर्ष 2019 में गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ा, जहाँ निवासियों को जल टैंकों और वलिवणीकरण संयंत्रों पर निर्भर रहना पड़ा। [बेंगलुरु में हाल ही में सामने आया जल संकट](#) भी इस मुद्दे की गंभीरता को उजागर करता है।
- **‘अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट’ और हरित स्थानों की कमी:** तीव्र शहरीकरण और हरित स्थानों (Green Spaces) की कमी के कारण ‘अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट’ (Urban Heat Island Effect) उत्पन्न हुआ है, जिससे तापमान और ऊर्जा की मांग में वृद्धि हुई है।
  - उदाहरण: दिल्ली में चरम [हीट वेव](#) के कारण शहर की [बजिली मांग मई 2024 में 8,000 मेगावाट से अधिक के रिकॉर्ड स्तर](#) पर पहुँच गई।
- **आग की घटनाओं में वृद्धि:** उचित अग्नि सुरक्षा अवसंरचना और जागरूकता की कमी के कारण शहर में [आग की घटनाओं](#) में वृद्धि हुई है।
  - शहरी क्षेत्रों का उच्च घनत्व और संकीर्ण पहुँच मार्ग आग संबंधी खतरे को बढ़ा देते हैं, जिससे आपातकालीन सेवाओं के लिये प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देना कठिन हो जाता है।
- **शहरी बाढ़ और जल निकासी अवसंरचना:** अपर्याप्त वर्षा जल निकासी प्रणालियाँ और प्राकृतिक जल निकायों के अतिक्रमण के कारण मानसून मौसम में [शहरी क्षेत्रों में पराश्र: बाढ़](#) की स्थिति उत्पन्न होती है।
  - भारत ने हाल के वर्षों में बाढ़ की बड़ी घटनाओं का सामना किया है, विशेष रूप से [हैदराबाद \(2020 एवं 2021\)](#), [चेन्नई \(नवंबर 2021\)](#), [बेंगलुरु एवं अहमदाबाद \(2022\)](#), [दिल्ली के कुछ भागों \(जुलाई 2023\)](#) और [नागपुर \(सितंबर 2023\)](#) में, जहाँ कई निवासियों को क्षेत्र से बाहर निकलने के लिये विवश होना पड़ा।

## शहरी क्षेत्रों से संबंधित प्रमुख सरकारी पहलें

- [स्मार्ट सटीज](#)
- [अमृत मशिन](#)
- [स्वच्छ भारत मशिन-शहरी](#)
- [प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी](#)
- आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम
- [दीन दयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मशिन \(DAY-NULM\)](#)

## भारत के शहरी परदृश्य को पुनर्जीवित करने के लिये आवश्यक रणनीतियाँ:

- **वितरित अपशिष्ट-से-ऊर्जा प्रणालियाँ (Distributed Waste-to-Energy Systems) और वकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियाँ (Decentralised Waste Management Systems):** समुदाय-आधारित अपशिष्ट प्रबंधन पहलों को प्रोत्साहित करना और अपशिष्ट संग्रहण, छँटाई एवं प्रसंस्करण के लिये [सार्वजनिक-नजीक़ी भागीदारी](#) को बढ़ावा देना।
  - ऐसे छोटे स्तर के अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्रों के विकास को प्रोत्साहन देना जो नगरपालिका ठोस अपशिष्ट को [बायोगैस](#) या [बजिली](#) जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तित करते हैं।
- **स्मार्ट जल प्रबंधन और पुनर्चक्रण अवसंरचना:** लीक का पता लगाने, जल वितरण को इष्टतम करने और कुशल जल उपयोग को बढ़ावा देने के लिये [स्मार्ट वाटर मीटरिंग](#) एवं [नगरपालिका प्रणालियों की तैनाती](#) करना।
  - इंडस्ट्रियल कूलिंग, लैंडस्केपिंग एवं फलशुगि जैसे गैर-पेय प्रयोजनों के लिये उपचारित [अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण](#) एवं पुनः उपयोग के लिये उन्नत अपशिष्ट जल उपचार और पुनर्चक्रण सुविधाओं में निवेश करना।

- अभ्यास प्रश्न:** संवहनीय विकास सुनिश्चित करने और तीव्र शहरीकरण की चुनौतियों का समाधान करने के लिये भारत अपने शहरी परदृश्य को किस प्रकार पुनर्जीवित कर सकता है?